

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र

प्रलिस के लयः

चुनाव आयोग, स्थानीय नकलय, जनप्रतनलधतलव अधनलयम, 1951

मेन्स के लयः

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और इसकी आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

[नरलवाचन आयोग](#) द्वारा राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के मुद्दे को उठाए जाने की संभावना है ।

आंतरिक लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है?

- **प्रतनलधतलवः** 'इंटर-पार्टी/अंतर-दलीय लोकतंत्र' के अभाव ने राजनीतिक दलों को संकीरण नरलकुश संरचनाओं में बदल दलल है । यह नागरकलं के राजनीतल में भाग लेने और चुनाव लड़ सकने के **समान राजनीतिक अधिकार** पर प्रतकलल प्रभाव डालता है ।
- **गुटबाज़ी में कमीः** इससे मज़बूत ज़मीनी संपर्क या जनाधार रखने वाले नेता को दल में दरकनार नहीं कथल जा सकेगा । जसलसे पार्टी के भीतर गुटबाज़ी और वभलजन का खतरा कम हो जाएगा । उदाहरण के लयल भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) छोड़कर शरद पवार ने राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) और ममता बनरजी ने अखलल भारतीय तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) का गठन कर लयल था ।
- **पारदरशतलः** पारदरशी प्रकरयलओं के साथ एक पारदरशी दलीय संरचना, **उपयुक्त टकलट वतलरण और उममीदवार चयन** को बढ़ावा देगी । ऐसे चयन पार्टी के कुछ शकतशलाली नेताओं की इच्छा पर आधारतल नहीं होंगे, बलकलवे समग्र रूप से पार्टी की पसंद का प्रतनलधतलव करेंगे ।
- **जवाबदेहतलः एक लोकतांत्रक दल अपने सदस्यों के प्रतलउत्तरदायी होगा,** क्योंकि अपनी कमयलं के कारण वे आगामी चुनावों में हार सकते हैं ।
- **सत्ता का वकेंद्रीकरणः प्रत्येक राजनीतिक दल की राज्य और स्थानीय नकलय स्तर की इकाइयलं होती हैं ।** दल में प्रत्येक स्तर पर चुनाव का आयोजन वभलनन स्तरों पर शकतल केंद्रों के नरलमाण का अवसर देगा । इससे सत्ता या शकतल का वकेंद्रीकरण हो सकेगा तथा ज़मीनी स्तर पर नरलणय लयल जा सकेंगे ।
- **राजनीतल का अपराधीकरणः** चूँकल भारत में चुनाव से पूरव उममीदवारों को टकलटों के वतलरण हेतु कोई सुव्यवस्थतल प्रकरयल मौजूद नहीं है, इसलयल उममीदवारों को बस उनके 'जीत सकने की कषमता' की एक अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर टकलट दलल जाते हैं । इससे धनबल-बाहुबल अथवा **आपराधिक पृष्ठभूमल वाले उममीदवारों** के चुनाव मैदान में उतरने की अतरकलत समस्या उत्पन्न हुई है ।

अंतर-पार्टी लोकतंत्र की कमी के कारणः

- **वंशवाद की राजनीतलः** अंतर-दलीय लोकतंत्र की कमी ने राजनीतिक दलों में **भाई-भतीजावाद (Nepotism)** की प्रवृत्तल में योगदान दलल है । **पार्टी के वरषलत नेताओं द्वारा अपने परवलर के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है ।**
- **राजनीतिक दलों की केंद्रीकृत संरचनाः** राजनीतिक दलों के कारयकरण का केंद्रीकृत स्वरूप और वर्ष 1985 में अधनलयमतल दल-बदल वरलधी कानून, राजनीतिक दलों के नरलवाचतल सदस्यों को राष्ट्रीय तथा राज्य वधलनमंडलों में अपने व्यकतगत पसंद या ववलक से मतदान करने को अवरुद्ध करता है ।
- **कानून की कमीः** वर्तमान में भारत में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतांत्रक वनलयमन के लयल कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है और एकमात्र शासी कानून '**लोक प्रतनलधतलव अधनलयम, 1951**' की धारा 29A द्वारा प्रदान कथल गया है, जो भारतीय नरलवाचन आयोग में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है । हालाँकल राजनीतिक दलों द्वारा अपने पदाधिकारयलं के चयन हेतु नयलमतल रूप से आंतरिक चुनाव आयोजतल कथल जाते हैं, कतल कसल दंडात्मक प्रावधान के अभाव में यह अत्यंत सीमतल ही है ।
- **व्यकतल पूजाः** प्रायः आम लोगों में नायक पूजा की प्रवृत्तल होती है और कई बार पूरी पार्टी पर कोई एक व्यकतल हावी हो जाता है जो अपनी मंडली बना लेता है, जसलसे सभी प्रकार के अंतर-दलीय लोकतंत्र का अंत हो जाता है । उदाहरण के लयल माओत्से तुंग का चीनी कमयुनसलट पार्टी पर आधपतय या अमेरकल में रपलबलकल पार्टी पर डोनालड ट्रंप का प्रभाव ।
- **आंतरिक चुनावों को अप्रभावी करनाः** पार्टी में शकतल समूहों द्वारा अपनी सत्ता को मज़बूत करने और यथास्थतल बनाए रखने के लयल आंतरिक

संस्थागत प्रक्रियाओं को नष्ट करना बेहद सरल है।

आंतरिक लोकतंत्र पर चुनाव आयोग के नरिदेश:

- **जनप्रतनिधित्व अधिनियम, 1951:**
 - चुनाव आयोग ने समय-समय पर जनप्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 A के तहत पार्टियों के पंजीकरण के लिये जारी दशा-नरिदेशों का उपयोग किया है ताकि पार्टियों को चुनाव कराने के लिये याद दलाया जा सके और **सुनिश्चित किया जा सके कि हर पाँच वर्ष में उनका नेतृत्व नवीनीकृत, बदला या फरि से नरिवाचति हो।**
- **पार्टी का संवधान:**
 - अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिये आवेदन करने वाले दलों हेतु चुनाव आयोग के दशा-नरिदेश में कहा गया है **कक्षावेदक को पार्टी संवधान की एक प्रत जिमा करनी चाहिये।**
 - चुनाव आयोग के दशा-नरिदेशों में कहा गया है, "वभिनिन स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों और ऐसे चुनावों की अवधतिथा पार्टी के पदाधिकारियों के पद की शरतों के संबंध में पार्टी के संवधान/नयिमों एवं वनियिमों/ज्जापन में एक वशिष्ट प्रावधान होना चाहिये।"
- **राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति:**
 - चुनाव आयोग ने **पूर्व में कानून मंत्रालय से राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति की मांग थी,** लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है।
- **किसी पार्टी के लिये कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं:**
 - भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने भी हाल ही में एक पार्टी के लिये 'स्थायी अध्यक्ष' के वचार को खारजि कर दिया है।
 - चुनाव आयोग का मानना है कि **ऐसा कदम स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र वरिधी है।**

आगे की राह

- मौजूदा कानूनों की **फरि से व्याख्या करने और कुछ साहसिक कदम उठाने** की आवश्यकता है, जैसे-
 - राजनीतिक दलों को नयिमति रूप से संगठनात्मक चुनाव कराने चाहिये।
 - राजनीतिक दलों को अपने पदाधिकारियों और उनके पते में **किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को सूचति करना आवश्यक हो।**
 - **इन्हें चुनाव के दौरान और उसके अलावा किये गए खर्च का एक दस्तावेज़ जिमा करना आवश्यक होना चाहिये।**
- यह **राजनीतिक दलों का करतव्य है कि सभी स्तरों पर** चुनाव का आयोजन सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाए जाएँ। राजनीतिक दलों को नरिवाचन आयोग द्वारा नामति पर्यवेकषकों की उपस्थिति में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के आंतरिक चुनाव संपन्न कराने चाहिये।
- नरिवाचन आयोग को आंतरिक चुनाव की आवश्यकता संबंधी किसी भी प्रावधान के **गैर-अनुपालन के आरोपों की जाँच की शक्ति** होने के साथ यदि राजनीतिक दल स्वतंत्र एवं नषिपक्ष रूप से चुनाव आयोजति नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में **नरिवाचन आयोग के पास दल का पंजीकरण रद्द करने की दंडात्मक शक्ति होनी चाहिये।**

स्रोत: द हिंदू